

‘सौ हाथों से कमाएं और...’, पीएम मोदी-रक्षामंत्री राजनाथ ने की सहयोग की अपील

नई दिल्ली। शहीदों और सीमाओं पर बहादुरी से लड़ने वाले जवानों को सम्मानित करने के लिए हर साल आज का दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत गौरव का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देश के जवानों की वीरता, दृढ़ संकल्प और बलिदान को सलाम किया है। साथ ही उन्होंने देश वासियों से शहीदों के परिजनों और जवानों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में सहयोग की भी अपील की है।

पीएम मोदी ने इस मौके पर एकस अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे साहसी सैनिकों की वीरता, दृढ़ संकल्प और



बलिदान को सलाम करने के बारे में है। उनकी बहादुरी हमें प्रेरित करती है, उनके बलिदान और उनका समर्पण हमें सुरक्षित रखता है। आइए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में भी योगदान करें।

सैनिकों का बलिदान और अनुशासन हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत

अपनी पोस्ट में आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे सैनिकों का बलिदान और

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोगों से की अपील

पीएम मोदी के अलावा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। एकस पर एक वॉडियो संदेश में, राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का दिन देश नागरिकों के लिए सैनिकों के अदम्य साहस, बलिदान और समर्पण को पहचानने और "बहादुरों" के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के संकल्प की पुष्टि करने का एक अवसर है। हमारे सशस्त्र बल एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, जो हर स्थिति में हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भले ही वह खतरा बाहरी हो, या प्राकृतिक आपदाएं।

अनुशासन हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान लोगों से

अपनी भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका योगदान सैनिकों और उनके परिजनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि समाज के कल्याण के लिए प्रत्येक नागरिक का

कर्तव्य है कि वह सौ हाथों से कमाएं और हजार हाथों से दान दे।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस का इतिहास

भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने के पीछे की एक खास वजह है। भारत कई दशकों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। हालांकि 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र घोषित हो गया। इसके बाद भारत का संविधान बना और यह एक लोकतांत्रिक देश बन गया। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी देश की सीमा की रक्षा करना। इसके लिए सेनाएं अस्तित्व में आईं, जिन्हें मजबूत किया जाने लगा। आजादी के दो साल बाद 28 अगस्त 1949 को भारत सरकार ने भारतीय सेना के जवानों के कल्याण के लिए एक

समिति का गठन किया। सेना के जवानों के कल्याण के लिए गठित समिति ने प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाने का फैसला लिया। इस समिति ने धन जमा करने के लिए लोगों के बीच छोटे झंडे बांटे और इससे चंद एकत्र किया। उस दौरान झंडे में तीन रंग (लाल, गहरा नीला और हल्का नीला) थे। ये रंग तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करते हैं। झंडे से चंदा एकत्र करके धमा जमा करने के पीछे समिति के तीन मुख्य उद्देश्य रहे। पहला, जंग के समय जनहानि पर सहयोग करना। दूसरा, सेना के कर्मियों और उनके परिवार का कल्याण व सहयोग करना और तीसरा, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार का कल्याण करना।

न्यूज गैलरी

पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम के कुछ प्रावधानों को दी गई 'सुप्रीम' चुनौती

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाओं में किसी पूजा स्थल को फिर से पाने या 15 अगस्त 1947 को प्रचलित स्वरूप में परिवर्तन की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाने वाले प्रावधानों को चुनौती दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ दोपहर 3.30 बजे मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-उत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस दावे कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं को लेकर आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी का हर 'वाहिनी', 'परिषद' और 'सेना' के पीछे एक अदृश्य हाथ है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को ऐसे इतिहास को लेकर लड़ई में धकेला जा रहा है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता, अगर उसकी 14 प्रतिशत आबादी इस तरह के लगातार दबाव का सामना करे।

पीरियड्स के दौरान छात्राओं को एक दिन की छुट्टी

गंगटोक। सिक्किम विश्वविद्यालय ने छात्राओं के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। पीरियड्स के दौरान छात्राओं को एक दिन के अवकाश की अनुमति दी गई है। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है। सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा पिछले माह एक प्रतिवेदन दिया गया था। इसके बाद सिक्किम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार लक्ष्मण शर्मा ने चार दिनों तक को इस आशय की अधिसूचना जारी की।

कांग्रेस को पसंद नहीं ममता का दावा लीडरशिप पर इंडिया गठबंधन में रार

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए तैयार इंडिया गठबंधन में महभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने जैसे ही इंडिया गठबंधन की लीडरशिप पर अपना दावा ठेका कि कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई। देश की सबसे पुरानी पार्टी को यह बात रास नहीं आई। हालांकि, ममता के दावे को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी (सपा) का समर्थन जरूर मिला है। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने लालू यादव को इस गठबंधन की शिल्पकार करार दिया है।

कांग्रेस का विरोध
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के दावे पर असहमति जताई। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि गठबंधन का नेतृत्व सामूहिक सहमति से तय किया जाना चाहिए, न कि किसी एकतरफ घोषणा से। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "गठबंधन का नेतृत्व एक सामूहिक निर्णय होना चाहिए और



इसे सभी सहयोगियों की सहमति से तय किया जाएगा।

समाजवादी पार्टी का रुख
समाजवादी पार्टी (एसपी) ने ममता के नेतृत्व का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ममता बनर्जी अपने नेतृत्व कौशल ने हरियाणा और महाराष्ट्र में लगातार चुनावी हार के बाद इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा, 'अगर ममता गठबंधन ने ऐसी इच्छा जाहिर की है तो इंडिया ब्लाक के नेताओं को उसपर विचार करना चाहिए और उनका सहयोग लेना चाहिए। इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। ममता बनर्जी ने भाजपा को बंगाल में रोकने का काम किया है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के प्रति हमारा 100

गठबंधन के सामने चुनौतियां

इन विभिन्न बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि विपक्षी दलों को एकजुट रहना चुनौतीपूर्ण होगा। गठबंधन ने अब तक ईवीएम छेड़छाड़ जैसे मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज उठाई है, लेकिन नेतृत्व को लेकर विवाद उनके सामूहिक उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। सियासी एक्सपर्ट का मानना है कि इन मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर हलाने के बजाय आंतरिक चर्चा में हल किया जाना चाहिए।

प्रतिशत समर्थन और सहयोग है।' **राजद का बयान**
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस बहस को अलग दिशा देते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ही गठबंधन के असली निर्माता हैं। राजद के प्रवक्ता ने कहा, "इंडिया गठबंधन किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पर नहीं बल्कि सामूहिक ताकत पर आधारित है। लालू प्रसाद यादव ने इस गठबंधन की नींव रखी थी और उनकी दृष्टि ही इसे आगे ले जाएगी।

स्कूल के मेन गेट पर लड़के को बांधकर शिक्षकों ने पीटा

भुवनेश्वर। ओडिशा में स्कूल के मेन गेट पर शिक्षकों की ओर से 7 वर्षीय लड़के को बांधकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को इसे लेकर जांच का आदेश दिया गया। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह घटना 25 नवंबर को केंद्रपाड़ा जिले के माशोर्षई पुलिस थाना क्षेत्र में एक निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हुई थी। घटना की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद यह मामला प्रकाश में आया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। कक्षा में कथित रूप से गड़बड़ी फैलाने के आरोप में लड़के को दंडित किया गया।

हिमंत बिस्व सरमा की कैबिनेट में विस्तार, चार मंत्रियों ने ली शपथ

गुवाहटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को चार मंत्रियों का शपथ लेने के साथ अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। सीएम सरमा के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चार नये मंत्रियां प्रशांत फूकन, कौशिक राय, कृष्णेंद्र पाँल और रूपेश गोआला हैं। ये सभी भाजपा के विधायक हैं। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री के साथ उनके कैबिनेट के अन्य मंत्री भी शामिल थे।

भाजपा नेता प्रशांत फूकन डिब्रूगढ़ से चार बार विधायक रह चुके हैं। कृष्णेंद्र पाँल पथारकांडी से दो बार, जबकि कौशिक राय और रूपेश गोआला क्रमशः लखीपुर और डूम डूमा से एक बार विधायक रह चुके हैं। इन नए मंत्रियों के शपथ के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अब 19 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं।



सीएम सरमा ने कहा, "हमारे मंत्रालय में बराक घाटी से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।आज हमने अपने मंत्रिपरिषद में चार मंत्रियों को शामिल किया है। एक पद अभी भी खाली है और उसे आने वाले दिनों भर दिया जाएगा। असम में कई विकास गतिविधियां चल रही है। चार मंत्रियों को शामिल किये जाने से मंत्रिपरिषद मजबूत हो गई है।"

असम पुलिस ने पांच बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा

अमेरिकियों द्वारा पिछले कई महीनों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अपराध का दस्तावेजीकरण करने के लिए बनाए गए www.stophindugenocide.org में कहा गया है, "बांग्लादेश में स्थिति केवल एक क्षेत्रीय संकट नहीं है; यह एक मानवीय आपदा है। नरसंहार मानवता के खिलाफ अपराध है। हस्तक्षेप करना, सुरक्षा करना और आगे के अत्याचारों को रोकना अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है।" हाल के दिनों में हिंदुओं के खिलाफ क्रूरता चौंकाने वाले स्तर

असम पुलिस ने बांग्लादेश से दो महिला समेत छह घुसपैठियों को पकड़ा और पड़ोसी देश के अधिकारियों को सौंप दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, असम पुलिस ने सतर्क कदम उठाते हुए छह बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ कर उन्हें वापस भेज दिया। उन सभी को सीमा पार भेज दिया गया। घुसपैठियों की पहचान मोहम्मद दीदारुल इस्लाम, संतू खान, इस्माइल हुसैन राहत, साकिब हुसैन, शांति अख्तर और मीम सरमा के तौर पर की गई है। मुख्यमंत्री ने यहा नहीं बताया कि इन सभी घुसपैठियों को भारत-बांग्लादेश सीमा के किस सेक्टर पर रोका गया था। अबतक भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करने के आरोप में 167 लोगों को पकड़ा गया है। बाद में उन्हें उनके देश वापस भेज दिया गया।

चरमपंथी हिंसा... सऊदी अरब और मलेशिया के जरिए 2.8 करोड़ रुपये की फंडिंग हुई

रोहिंग्या आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट? भारत की चिंता बड़ी

ढाका। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों को आतंकी ट्रेनिंग देने की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इन्हें ट्रेनिंग देने के बाद म्यांमार में जारी गुहयुद्ध में शामिल होने के लिए भेजा जाता है। बता दें कि भारत के पड़ोसी देश में श्रेष्ठ हसीना सरकार के पतन के बाद से चरमपंथी हिंसा बढ़ती जा रही है। अब रोहिंग्याओं को आतंकी बनाने की खबरें चौंकाने वाली हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश का कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन से रोहिंग्या शरणार्थियों को आतंकी गतिविधियों

के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। 250 से ज्यादा रोहिंग्याओं को ट्रेन किया जा रहा है। इसके लिए सऊदी अरब और मलेशिया के जरिए 2.8 करोड़ रुपये की फंडिंग हुई है। यह खतरनाक घटनाक्रम क्षेत्रीय शांति को अस्थिर कर सकता है और भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है।

आतंकवाद की ओर बढ़ते कदम

रोहिंग्याओं को बांग्लादेश में ट्रेनिंग दी जा रही है और म्यांमार में लड़ने के लिए भेजा रहा है। बांग्लादेश में स्थिते दुनिया के सबसे



बड़े शरणार्थी शिविर कॉक्स बाजार से जुलाई में 32 वर्षीय रफीक ने नाव के जरिए म्यांमार की सीमा पार की। उसका मकसद म्यांमार में चल

रहे गुहयुद्ध में शामिल होना था। रफीक ने बताया, "हमें अपनी जमीन वापस पाने के लिए लड़ना होगा। और कोई रास्ता नहीं है।"

क्षेत्रीय अस्थिरता और भारत के लिए चिंता
इस पूरे घटनाक्रम से भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच अस्थिरता का प्रभाव न केवल पूर्वोत्तर भारत पर पड़ेगा, बल्कि आतंकवादी गतिविधियों के जरिए क्षेत्रीय शांति पर भी असर होगा। बांग्लादेश के लिए यह स्थिति एक "टिकिंग टाइम बम" बन चुकी है, क्योंकि हिंसा और उग्रवाद की बढ़ती घटनाएं शरणार्थियों की वापसी के प्रयासों को और जटिल बना रही हैं। कुल मिलाकर रोहिंग्या संकट अब एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बन चुका है, जिसमें आतंकवाद, शरणार्थी संकट, और क्षेत्रीय अस्थिरता के कई पहलू शामिल हैं। भारत समेत क्षेत्रीय देशों को मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा, ताकि मानवता और शांति को बचाया जा सके।

कॉक्स बाजार के शिविरों में इस साल उग्रवादी गतिविधियों और

भर्ती में तेजी देखी गई है। चार विश्वसनीय सूत्रों और दो आंतरिक

एजेंसी रिपोर्टों के अनुसार, शिविरों में हिंसा और उग्रवाद का स्तर बढ़ता जा रहा है। रोहिंग्या मुख्य रूप से मुस्लिम समूह है जो दुनिया की सबसे बड़ी देशविहीन आबादी है। इस आबादी ने 2016 में बौद्ध-बहुल म्यांमार की सेना के हाथों नरसंहार से बचने के लिए बांग्लादेश की ओर भागना शुरू कर दिया था। तब से वे भारत और बांग्लादेश सहित कई देशों में विभिन्न जगहों पर बसे हुए हैं। 2021 में सेना द्वारा तख्तापट्ट किए जाने के बाद से म्यांमार में लंबे समय से चल रहे विद्रोह ने

जोर पकड़ लिया है। इसमें कई सशस्त्र समूह हैं। इसमें अब रोहिंग्या लड़के भी शामिल हो गए हैं। ये लड़के उसी म्यांमारी सेना के साथ मिलकर लड़ रहे हैं जिसने कभी उन पर अत्याचार किया था। इसकी वजह अराकान आर्मी (एए) को बताया जा रहा है। कहा जाता है कि अराकान आर्मी (एए) ने भी रोहिंग्याओं पर अत्याचार किए थे और उन्हें भागने के लिए मजबूर किया। अब रोहिंग्या अपने पूर्व सैन्य उत्पीड़कों के साथ मिलकर अराकान आर्मी से लड़ने के लिए समूहों में शामिल हो गए हैं।

■ न्यूज गैलरी

13 दिसंबर को होगी भोपाल निगम परिषद की मीटिंग



भोपाल/नवप्रदेश। भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग की डेट फाइनल हो गई है। यह 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगी। एमआईसी से मंजूर 21 मुद्दों के प्रस्ताव को परिषद की मीटिंग में रखेंगे। नियमानुसार दो महीने में मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन यह 3 महीने के बाद होगी। ऐसे में विपक्ष हंगामा कर सकता है। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया, परिषद की मीटिंग में निर्धारित एजेंडे पर चर्चा की जाएगी।

बता दें कि नगर निगम परिषद की मीटिंग की तारीख तय नहीं होने से सियासत गरमा गई थी। कांग्रेस पार्षद खुलकर शहर सरकार पर आरोप लगा रहे थे। इसी बीच शुक्रवार को एमआईसी (मेयर इन कौंसिल) की मीटिंग में 22 में से 21 विषयों को मंजूरी दे दी गई। एमआईसी के बाद परिषद की मीटिंग की तारीख भी तय कर ली गई। हालांकि, शनिवार को यह डेट सामने आई।

एमआईसी बैठक में शाहपुरा तालाब, अमृत-2 जैसे 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। शाहपुरा तालाब का सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित करने का भी निर्णय लिया गया है। यहां फुटपाथ निर्माण के साइथ ही तालाब में मिलने वाले सीवेज के पानी को रोकने बंदोबस्त किए जाएंगे। इस पर 9.16 करोड़ रुपए खर्च होगा। स्मार्ट नेविगेशन डिवाइस लगाने वाली कंपनी यूनिर्कॉर्न सॉल्यूशन का एग्रीमेंट खत्म कर उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। ऐसे में शहर में लगी 100 से ज्यादा इन गेट्री का संचालन नगर निगम की ओर से किया जाएगा। यही नहीं, अमृत प्रोजेक्ट के तहत शहर में 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से पानी की पाइपलाइन बिछाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। यही प्रस्ताव अब परिषद की मीटिंग में रखे जाएंगे। अफसरों और एमआईसी सदस्यों के बीच पिछले ढाई महीने से चल रहे विवाद पर भी विराम लग गया है। अपर आयुक्त देवेन्द्र सिंह चौहान को हटाने की जिद पर अड़े एमआईसी सदस्यों ने स्वच्छ सर्वे की तैयारियों को देखते हुए अपनी मांग छोड़ दी। सूत्र बताते हैं कि, निगम कमिश्नर हरेन्द्र नारायण यादव ने चौहान को बदलने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए टीम आने वाली है। ऐसे में अचानक प्रभाी नहीं बदल सकते। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने कहा कि परिषद की पिछली मीटिंग 2 सितंबर को हुई थी। नियमानुसार अगली मीटिंग 2 नवंबर को होनी चाहिए थी, लेकिन 3 महीने से अधिक समय बीत गया है। बता दें कि मीटिंग नहीं होने से कांग्रेसी पार्षद भोपाल कमिश्नर संजीव सिंह के पास भी पहुंचे। सियासत के बीच अब मीटिंग की तारीख तय हो गई है।

कुबेरेश्वरधाम पर शिव महापुराण का आयोजन



जो नियमों का पालन करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं- पंडित राघव मिश्रा

सीहोर/नवप्रदेश। मनुष्य भगवान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, अक्सर हम भगवान द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं। जिसके कारण हमें दुखों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भगवान की शरण में जाने से ही मनुष्य के जीवन का कल्याण होता है। यह विचार चिंताबलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर एवं कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार से आरंभ हुई संगीतमय शिव महापुराण के पहले दिन कथा व्यास राघव मिश्रा ने कहे। बीते दिनों सीहोर से बाहर महाराष्ट्र में कथा से लौटे कथा व्यास राघव मिश्रा का विठ्ठलेश सेवा समिति के द्वारा भव्य स्वागत किया गया था, अपने पिता श्रीकथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मार्ग दर्शन में शनिवार से शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को नियमित रूप से भोजन प्रसादी का वितरण निशुल्क रूप से किया जा रहा है। कथा के पहले दिन श्रद्धालुओं के मध्य पहुंचे पंडित राघव मिश्रा का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि एक घड़ी के सत्संग की तुलना स्वर्ग की समस्त संपदा से की गई है। भगवान शिव भी सत्संग का महत्व मां पार्वती को बताते हुए कहते हैं कि उसकी विद्या, धन, बल, भाग्य सब कुछ निरर्थक है जिसे जीवन में संत की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन वास्तव में सत्संग कहते किसे हैं। सत्संग दो शब्दों के जोड़ से मिलकर बना यह शब्द हमें सत्य यानि परमात्मा और संग अर्थात् मिलन की ओर इर्शित करता है।

परमात्मा से मिलन के लिए संत एक मध्यस्थ है, इसलिए हमें जीवन में पूर्ण संत की खोज में अग्रसर होना चाहिए, जो हमारा मिलाप परमात्मा से करवा दे। शिव महापुराण मानव जाति को सुख-समृद्धि व आनंद देने वाली है। क्योंकि भगवान शिव कल्याण एवं सुख के मूल स्रोत हैं।

स्कूल स्टाफ ने लड़कों से करवाई प्रिंसिपल की हत्या: भाई ने लगाया आरोप

गोली मारने के बाद भागा दूसरा भी हिरासत में

छतरपुर/नवप्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शुक्रवार को तीन दिन की छुट्टी के बाद वापस आए प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार सक्सेना की स्कूल में 12वीं के छात्र ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामला शुक्रवार दोपहर 1 बजे धर्मोरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का है। वारदात के बाद आरोपी छात्र प्रिंसिपल की स्कूटी लेकर भाग निकला। हालांकि पुलिस ने वारदात के कुछ घंटे बाद ही आरोपी छात्र को नौगांव से पकड़ लिया। इसके अलावा दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है।

दो पाइंट में पुलिस की जांच समझिए

पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह आरोपी छात्र स्कूल आया था। दोपहर में लंच के बाद वह प्रिंसिपल के कक्ष में घुसा, लेकिन प्रिंसिपल वहां नहीं थे। इस दौरान छात्रों से पूछा कि सर कहाँ हैं तो उसे बाथरूम की ओर जाने का कह दिया। इसके बाद वह बाथरूम की ओर गया और उन पर पीछे से फायर कर दिया। गोली प्रिंसिपल के सिर में लगी, वे सीधे



सुरेंद्र सक्सेना, प्रिंसिपल

पीछे की तरफ गिरे। पास में ही बाथरूम गए छात्र चीखते हुए वहां से भाग निकले।

पुलिस के अनुसार आरोपी ने वहां खड़े लोगों को भी धमकाया कि यदि कुछ बोला तो गोली मार दूंगा। इसके बाद कट्टा लहराते हुए प्रिंसिपल की स्कूटी की चाबी ली। बच्चों को धमकाते हुए स्कूटी स्टार्ट कर वहां से फरार हो गया। आरोपी की धमकी और कट्टा हाथ में देखकर सभी टीचर ने बच्चों को लेकर क्लास में अंदर कर दरवाजा बंद कर लिया

था। आरोपी के जाने के बाद दरवाजा खोला और पुलिस को जानकारी दी।

राजनीतिक दबाव के कारण अपराधियों को बचा रही है पुलिस

मृतक के भाई राजेंद्र सक्सेना ने आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। इन आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण है, इसीलिए कोई भी इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। इसीलिए पुलिस

दूसरे आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है।

छात्रों ने कहा-आए दिन कमेट करता था आरोपी

प्रिंसिपल की हत्या के बाद पुलिस पूछताछ में स्कूल के छात्रों ने बताया कि आरोपी स्कूल की छात्राओं पर कमेट कर छोड़छाड़ करता था। इसकी शिकायत छात्राओं ने टीचर और प्रिंसिपल से की थी। प्रिंसिपल ने छात्र को सख्ती से समझाया था, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। इस पर प्रिंसिपल ने उसके परिजनों को स्कूल बुलाकर बेटे की शिकायत की थी। उसने टीचर के समझाने पर उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी थी। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ने छात्र के पिता को कई बार बुलाकर शिकायत की थी। कहा था कि आपका बेटा अनुशासनहीन है। इसे संभाल लो। तब से ही वह प्रिंसिपल से नाराज था। आरोपी पिछले एक सप्ताह से कट्टा लेकर स्कूल में आ रहा था। उसने सभी को धमकाया था। उसने कहा था कि प्रिंसिपल और जिस टीचर ने मेरे परिवार से शिकायत

की है, उन्हें जान से मार दूंगा।

प्रिंसिपल के भाई ने कहा , 4-5 साल से पोस्टेड थे

प्रिंसिपल के छोटे भाई राजेंद्र सक्सेना ने कहा कि मेरे भाई इसी स्कूल में करीब 4-5 साल से पोस्टेड थे, लेकिन कुछ लोग उन पर अनावश्यक दबाव डालते थे। गलत काम करवाने के लिए उनको प्रताड़ित करते थे। स्कूल का गेट हमेशा बंद रहता है, लेकिन आज खुला रखा गया। कोई भी एंट्री करे, कोई भी चला जाए। मुझे लगता है कि यह प्लान के तहत मर्डर करवाया गया है, ताकि आरोपी वारदात कर आसानी से भाग सके।

डॉक्टर बोले-एक गोली आरपार हो गई

शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर आनंद त्रिपाठी का कहना है कि एक गोली आरपार हो गई है, जबकि दूसरी गोली उनके सिर में फंसी हुई है। इसकी डिटेल जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी जाएगी। प्रिंसिपल सुरेंद्र सक्सेना की मौत गोली लगने से ही हुई है।

एम्स में शुरू होंगे हाइब्रिड कार्डियक ऑपरेटिंग रूम्स, हृदय रोग के मरीजों की सर्जरी होगी आसान

एम्स में आने वाले हृदय रोग से संबंधित मरीजों के लिए अच्छी खबर है। यहां जल्द ही अत्याधुनिक हाइब्रिड कार्डियक ऑपरेटिंग रूम्स शुरू किए जाएंगे। इसको लेकर डॉ. विक्रम वट्टी ने कॉन्फ्रेंसिटल एंड स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया।



के डॉ. वट्टी ने हाइब्रिड कार्डियक ऑपरेटिंग रूम्स की भूमिका और इसके आधुनिक हृदय देखभाल में योगदान के बारे में अपने विचार साझा किए। हाइब्रिड कार्डियक ऑपरेटिंग रूम्स एक अत्याधुनिक सर्जिकल सुइट है, जिसमें उन्नत इमेजिंग तकनीक और सभी सुविधाओं से युक्त ऑपरेटिंग रूम की सुविधाएं एक साथ मिलती हैं। इस नवाचार के माध्यम से डॉक्टर पारंपरिक सर्जिकल प्रक्रियाओं और मिनिमली इनवेसिव इंटरवेंशनल टेक्निक्स को एक ही स्थान पर बिना किसी विघ्न के कर सकते हैं। हाइब्रिड कार्डियक सर्जरी का उपयोग विभिन्न हृदय रोगों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि एंजोवैस्कुलर एओर्टिक रिपेयर, हाइब्रिड कोरोनरी आर्टरी रिवास्कुलराइजेशन, हाइब्रिड एरिथमिया प्रक्रियाएं, और हाइब्रिड कॉन्फ्रेंसिटल प्रक्रियाएं।

डॉ. वट्टी ने कहा कि हाइब्रिड कार्डियक सर्जरी के कई लाभ हैं, जैसे कि सर्जिकल जटिलताओं का जोखिम कम होना, रिकवरी में कम समय लगना। इस कारण मरीजों एवं उनके परिवारों को भी कम तनाव होगा। हाइब्रिड सर्जरी को एक स्टेज या दो स्टेज प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है। एक स्टेज प्रक्रिया में सभी उपचार एक ही सत्र में किए जाते हैं, जबकि दो स्टेज प्रक्रिया में कैथिटर-बेस्ड इंटरवेंशंस और शल्य चिकित्सा के बीच एक अंतराल होता है। मद्रास मेडिकल मिशन ने देश भर से 20 कार्डियोलॉजिस्ट को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि, डॉ. विक्रम वट्टी इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में आमंत्रित होने वाले एकमात्र कार्डियक सर्जन थे। यह कार्यक्रम मद्रास मेडिकल मिशन के डॉ. के. शिव कुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया

नशामुक्ति अभियान, छात्राओं ने ली शपथ: एसडीओपी बोले- इससे परिवार हो रहे बर्बाद

यातायात और साइबर सुरक्षा के बारे में भी बताया

भिंड/नवप्रदेश। भिंड के मेहागांव थाना पुलिस ने कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को नशा मुक्ति अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्राओं को नशे के दुष्परिणाम समझाए और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। एसडीओपी संजय कोच्छ, एसआई वंदना शर्मा, और एसआई विवेक शर्मा ने छात्राओं को संबोधित किया। एसडीओपी संजय कोच्छ ने कहा कि नशामुक्ति में विद्यार्थियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्राओं से अपील की कि वे न सिर्फ खुद नशे



से बचें बल्कि अन्य लोगों को भी इसके खिलाफ जागरूक करें। उन्होंने कहा कि अवैध मादक पदार्थों की

तस्करी की जानकारी पुलिस को दें ताकि ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। नशे से परिवार

बर्बाद हो रहे हैं।

यातायात और साइबर सुरक्षा के बारे में भी बताया

कार्यक्रम में यातायात नियमों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया गया। एसआई वंदना शर्मा ने साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी देते हुए बताया कि छात्राएं इंटरनेट पर किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती न करें और अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें।

छात्राओं को उनके प्रति होने वाले अपराधों और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि किसी भी सदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें।

भोपाल में बहन को छेड़ने से रोका तो मार डाला

युवक को किडनैप कर

कॉन्स्टेबल के नंबर से मांगी

फिरौती; 5 दिन बाद मिली लाश

भोपाल/नवप्रदेश। भोपाल में एक युवक ने बहन से छेड़छाड़ कर रहे बदमाश को टोका तो उसने किडनैप कर लिया। फिर एक कॉन्स्टेबल के नाम की सिम से बहन को कॉल करके एक लाख रुपए की फिरौती मांगी। पांच दिन बाद युवक की लाश 50 किलोमीटर दूर रातापानी के जंगल में मिली। पुलिस को आशंका है कि उसकी तीन-चार दिन पहले हत्या की गई है। युवक राजधानी के छोला मंदिर इलाके में किएा का कमरा लेकर रहता था।

पुलिस ने बताया कि बिहार पुलिस का वांटेड अवैकश भोपाल के छोला मंदिर इलाके में फरारी काट रहा था। ऑटो चालक संदीप प्रजापति भी यहीं किएा का कमरा लेकर रहता था। अवैकश उसकी बहन को परेशान कर रहा था। संदीप ने उसे इस बात पर टोका था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। छोला मंदिर टीआई



सुरेशचंद्र नागर ने बताया कि अवैकश की लोकेशन मुरैना में ट्रेस की गई। अगले कॉल में फिर फिरौती मांगी गई। इस बार कॉलर की लोकेशन नागपुर में ट्रेस की गई। आरोपी ने मुरैना के जिस नंबर से धमकाया, वह ग्वालियर के जनकगंज थाने में पदस्थ एक कॉन्स्टेबल के नाम रजिस्टर्ड है। पुलिस ने कॉन्स्टेबल से संपर्क किया तो उसने बताया कि ये नंबर वह दो साल पहले बंद कर चुका है। कंपनी की ओर से सिम किसी और को अलॉट की गई होगी, लेकिन दस्तावेज अपडेट नहीं किए गए हैं। पुलिस की 3 टीमों आरोपी की तलाश में जुटी रहीं। एक टीम नागपुर, दूसरी मुरैना और तीसरी देलावाड़ी में अवैकश की तलाश करती रहीं। पुलिस को आशंका थी कि पहले कॉल में देलावाड़ी में एक्सीडेंट की

संदीप की बहन ने आवाज से अवैकश को पहचान लिया। फिर उसने अपने पिता को मामले की जानकारी दी और थाने में शिकायत दर्ज कराई।

कॉन्स्टेबल दो साल पहले बंद कर चुका नंबर

पुलिस जांच में फिरौती वाले कॉल की लोकेशन मुरैना में ट्रेस की गई। अगले कॉल में फिर फिरौती मांगी गई। इस बार कॉलर की लोकेशन नागपुर में ट्रेस की गई। आरोपी ने मुरैना के जिस नंबर से धमकाया, वह ग्वालियर के जनकगंज थाने में पदस्थ एक कॉन्स्टेबल के नाम रजिस्टर्ड है। पुलिस ने कॉन्स्टेबल से संपर्क किया तो उसने बताया कि ये नंबर वह दो साल पहले बंद कर चुका है। कंपनी की ओर से सिम किसी और को अलॉट की गई होगी, लेकिन दस्तावेज अपडेट नहीं किए गए हैं। पुलिस की 3 टीमों आरोपी की तलाश में जुटी रहीं। एक टीम नागपुर, दूसरी मुरैना और तीसरी देलावाड़ी में अवैकश की तलाश करती रहीं। पुलिस को आशंका थी कि पहले कॉल में देलावाड़ी में एक्सीडेंट की

बात कही गई है। लिहाजा 3 दिन तक लगातार देलावाड़ी के जंगलों में सर्चिंग जारी रही। शुक्रवार को संदीप की लाश बरामद कर ली गई। लाश करीब तीन-चार दिन पुरानी बताई जा रही है।

आरोपी को खिलाफ कई केस, बिहार से फरार है

पुलिस जांच में सामने आया कि अवैकश पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार से 2 साल से फरार चल रहा है। बिहार पुलिस ने उसे वांटेड घोषित किया है। पुलिस का कहना है कि अवैकश, संदीप को 6 साल से जानता है। उसके पारिवारिक रिश्ते हैं। अवैकश उसकी बहन पर बुरी नजर रखने लगा था और उसे परेशान भी करता था। इसकी जानकारी मिलने पर संदीप और अवैकश के बीच विवाद हो चुका था। बदला लेने की नीयत से प्लानिंग के तहत संदीप की हत्या की गई। आरोपी की तलाश में पुलिस की चार टीमों जुटी हैं। सूचना के आधार पर इंदौर के एक ठिकाने पर दबिश दी गई थी, लेकिन अवैकश नहीं मिला।

पिता ने रस्सी से गला घोटकर की बेटे की हत्या: 30 हजार नहीं देने पर युवक कर रहा था मारपीट

भोपाल/नवप्रदेश। भोपाल के हनुमानगंज इलाके में एक पिता ने अपने बेटे की रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी। घटना का पता चलते ही मृतक की मां थाने पहुंची और पूरी बात पुलिस को बता दी। इसके बाद घर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को अरेस्ट कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज कर लिया। घटना शुक्रवार शाम की है। टीआई अवधेश सिंह भदौरिया के मुताबिक, हेमंत पिता वृंदावन नामदेव (28) बाल बिहार में रहता था। वह पिता वृंदावन नामदेव टेलर का काम करते थे। शुक्रवार शाम हेमंत की मां



दुर्गा बाई थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि उसके बेटे की हत्या पति

ने कर दी है। घटना की खबर लगते ही घर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया। साथ ही पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

30 हजार रुपए नहीं देने पर युवक कर रहा था मारपीट

मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि, बेटा मानसिक रूप से बीमार था और आए दिन माता-पिता के साथ मारपीट किया करता था। शुक्रवार शाम को बेटे ने पहले बीयर की मांग की, जिस पर पिता ने उसे बियर लाकर दे दी। इसके बाद हेमंत पिता को 30 हजार रुपए देने

को कहने लगा। मना करने पर वो मारपीट करने लगा। जिससे परेशान होकर उसने नाथलोन की रस्सी से गला घोटकर बेटे की हत्या की है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। आज पीएम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

परिजन के मुताबिक हेमंत उर्फ हनी बचपन से ही मानसिक रूप से बीमार था। जब से वो जवान अवस्था में आया तो गलत संगत में पड़ गया। नशे का आदी हो गया था। बार-बार घर वालों से पैसों की डिमांड करता था। हनी के पिता एक दर्जी हैं और

छोटा भाई योगेश की दुकान में काम करता है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। जिससे वो हनी की मांग पूरा नहीं कर सकते थे। जिससे वो माता-पिता के साथ मारपीट करता था।

बेटे की हत्या की सूचना मां ने थाने में पहुंचने के बाद पुलिस को दी थी। बताया कि पति ने उनके बेटे की हत्या कर दी है। वह हमें पीट रहा था, घर का सारा सामान तोड़ चुका था। आए दिन परेशान करता था। रात करीब 8 बजे उसने नशे में अपने पिता पर हाथ उठाया, वह परेशान हो चुके थे। इस कारण उसकी हत्या कर दी।



■ न्यूज गैलरी

लोधी वर-वधु परिचय सम्मेलन 8 को

रायपुर/नवप्रदेश। श्री नवयुवक लोधी मिलन समारोह समिति ,गोंदिया के तत्वावधान में रविवार , 8 दिसंबर को युवक-युवति परिचय सम्मेलन (वर्ष 36) का आयोजन जे. एम. हाय स्कूल, गणेश नगर गोंदिया में किया जा रहा है । इसका कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक भेरसिंह नागपूर एवं उद्घाटन एड. यीशुलालजी उपराडे, जिलाध्यक्ष भाजपा के द्वारा किया जाएगा । प्रमुख अतिथि विधायक राजकुमारजी कराहे एवं विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित सांसद डॉ. प्रशांतजी पडोडे एवं विधायक मा. विनोदजी अग्रवाल का जाहिर सत्कार किया जायेगा। मध्य भारत के सबसे बड़े लोधी समाज सम्मेलन में न केवल गोंदिया-भंडारा बल्कि नागपुर, चंदपुर, अमरावती, गर्डचरोली, बालाघाट, शिवनी, जबलपुर , छिंदवाड़ा एवं रसईहपुर से भी बड़ी संख्या में स्वजातीय बंधु उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में युवक- युवती परिचय, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं बच्चों के खेलकूद के कार्यक्रम लिये जाएंगे। प्रावीण्य प्राप्त विद्यार्थियों का सत्कार एवं प्रसिद्ध लोधी गौरव पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

सी.एस.के. स्कूल ने वृद्धाश्रम में गर्म कपड़े बांटे



रायपुर/नवप्रदेश। दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। दान एक सर्वोच्च गुण है और वह महान माध्यम है जिसके माध्यम से ईश्वर की दया मानव जाति तक पहुंचती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सी.एस.के. स्कूल रावतपुरा कॉलोनी फेस वन के बच्चों द्वारा माना कैंप स्थित वृद्धाश्रम में शनिवार को स्कूल के बच्चों द्वारा गर्म कपड़ों का दान किया गया। इसमें स्कूल के अभिभावकों और शिक्षिकाओं ने गर्म कपड़े दान कर अपनी अहम भूमिका निभाई। क्लास पी पी 2के बच्चों केव्यांश ,रुद्रांश ,वीरेंद्र ,तीक्षा द्वारा गर्म कपड़ों का दान किया गया।

70 लीटर देशी शराब जळ

रायपुर/नवप्रदेश। सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. शंशीता एवं कलेक्टर श्री गौरव सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग जिला रायपुर द्वारा अवैध मदिरा के निरुद्ध कार्यवाहियाँ जारी हैं । इसी अनुक्रम में कपोजिट देशी मदिरा दुकान गंजपारा के पास आरोपी अमन सोनी के आधिपत्य से 390 नग पाव (70.2 बल्क लीटर) देशी मदिरा मसाला शोले जप्त कर

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),59(क) का प्रकरण कायम कर आरोपी को जेल दाखिल किया गया । उल्लेखनीय है कि लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि गंजपारा में प्रातः 5:00 बजे से कुछ लोगों द्वारा अवैध मदिरा विक्रय किया जाता है, आरोपी अमन से पृच्छाछ करने पर उसने बताया कि आसपास के कई देशी मदिरा दुकान से इकट्ठा करते हैं तथा रात्रि में दुकान बंद होने के बाद एवं प्रातः दुकान खुलने से पहले तक घूम घूम कर विक्रय करते हैं।

हॉस्पिटल में मरीज को ब्लड चढ़ाने में देरी, एक कॉल में समस्या हुई दूर

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में रायपुर जिला प्रशासन द्वारा एक फोन कॉल पर समस्या का निराकरण हो रहा है। रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती मरीज त्रिलोकी वर्मा के भतीजे हेमराज वर्मा ने कलेक्टरेट के जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर में किया। श्री वर्मा ने कॉल सेंटर में फोन कर जानकारी दी कि उनके चाचा रिम्स हॉस्पिटल में एड्मिट हैं, उन्हें ब्लड चढ़ाने के लिए देरी की जा रही थी और अस्पताल प्रबंधन द्वारा भी रिस्पांस नहीं दिया जा रहा था। जिसके बाद श्री वर्मा ने कॉल सेंटर में कॉल कर पूरी मामले की जानकारी दी। इसके बाद तत्काल कार्रवाई प्रारंभ करते हुए अस्पताल प्रबंधन से मदद कराई गई और उन्हें तत्काल ब्लड चढ़ाया गया।

प्रेस कांफ्रेंस में बोले- धान खरीदी की तारीख 15 दिन और बढ़ाई जाए

धान खरीदी की परेशानियों को लेकर 10 दिसंबर को कांग्रेस का धरना

रायपुर/नवप्रदेश। राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा ने संयुक्त पत्रकारवार्ता को संबोधित किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुये कहा कि धान बेचने में किसानों को हो रही परेशानी तथा सरकार के किसान विरोधी रवैये के विरोध में कांग्रेस पार्टी 10 दिसंबर को प्रदेश के सभी ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन करेगी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने धान खरीदी केन्द्र चलो अभियान चलाया। जिसमें हमारे सभी नेता पदाधिकारी धान खरीदी केन्द्रों में गये हैं भी चार सोसायटी गया। पूरे प्रदेश में धान खरीदी केन्द्रों में अव्यवस्था किसान परेशान है। सरकार की कोशिश है कम से कम धान खरीदी को जाये।

सोसायटियों में हमारे नेताओं ने देखा कि बारदाने की कमी है, जिससे किसानों को धान बेचने में परेशान होना पड़ रहा। सरकार ने कहा है कि 50 प्रतिशत नये, 50 प्रतिशत पुराने बारदानों का उपयोग किया जाये। 50 प्रतिशत पुराने बारदाने समितियों में पहुंचे ही नहीं है, जिसके कारण धान खरीदी बाधित हो रही है। पुराने बारदाने पटे हुये है जिसमें धान भरा ही नहीं जा सकता, किसानों से कहा जा रहा 50 प्रतिशत बारदानो की व्यवस्था स्वयं करो उसका भुगतान किया जायेगा, लेकिन किसानो के बारदाने का पैसा भी नहीं मिल रहा। टोकन की व्यवस्था अव्यवहारिक है, जिससे किसानों को परेशान होना पड़ रहा, नंबर ही नहीं आ रहा। टोकन कटने की तारीख से 7 से 10 दिन बाद धान बेचने के लिये किसानों को बुलाया जा रहा है। 15 दिन बाद तक



का भी टोकन नहीं मिल रहा। इलेक्ट्रॉनिक कांटा में जो तौलाई हो रहा है उसमें 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम अधिक तौला जा रहा है। सोसायटियों में धान का उठाव नहीं होने के कारण जगह की कमी है। धान के बोरे जाम है। जगह का अभाव हो गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अनावरी रिपोर्ट कम बनाई गयी है तथा खरीदी भी 21 क्रिंटल के हिसाब से नहीं हो रही है। किसानों से पूरा धान नहीं खरीदा जा रहा है।

अनावरी रिपोर्ट गलत बनाया जा रहा जिसके आधार पर मात्र 9 से 12-14 क्रिंटल धान खरीदा जा रहा। किसानो से पूरा 21 क्रिंटल धान नहीं खरीदा जा रहा है। बड़े किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे उनकी बारी ही नहीं आ रही है। सरकार ने यह घोषणा किया है कि 72 घंटे में किसानों के खाते में पैसा आयेगा, लेकिन जो लोग धान बेच चुके है, उनके खाते के रकम हफ्तो तक नहीं आया है, जो रकम आ रहा है वह एक मुश्त 3100 नहीं है। सिर्फ 2300 रू.

प्रति क्रिंटल ही आ रहा है। (जो समर्थन मूल्य है उतना) भाजपा ने 3100 रू. एक मुश्त देने का वादा किया था।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हमारी मांग है धान की कीमत का भुगतान 3217 रू. में करें क्योंकि 3100 रू. भाजपा ने अपने चुनावी वायदे में कहा था। इस वर्ष केन्द्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 117 रू. बढ़ा दिया है। इस कारण इस वर्ष धान की खरीदी 3100 रू. से बढ़कर 3217 रू. किया जाये। कांग्रेस के समय भी कांग्रेस ने धान का समर्थन मूल्य 2500 देने का वादा किया था, लेकिन समर्थन मूल्य बढ़ने पर कांग्रेस ने 2640 रू. में धान खरीदी किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीज उत्पादक किसानों से सोसायटी में धान नहीं

खरीदा जा रहा। सोसायटी में सूचना चप्सा किया गया है कि बीज उत्पादक किसानों का धान नहीं लिया जायेगा। सोसायटी से धान संग्रहण केंद्रों में भेजा जा रहा है जबकि यह सीधे मिलरों के पास जाना चाहिये। इस कारण सोसायटी में संग्रहण केंद्रों के बीच परिवहन की लागत अतिरिक्त आ रही है। लेबर चार्ज बढ़ गया इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पिछले वर्ष का सुखत का पैसा सोसायटियों को अभी तक नहीं दिया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने कहा कि धान खरीदी में टोकन की व्यवस्था पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार आवाज उठाने के बाद सरकार ने 60-40 प्रतिशत आदेश दिया है। ऐप में देखा कि 15 जनवरी तक टोकन 60 प्रतिशत तक भरा हुआ है जबकि 31 जनवरी आखिरी तारीख है।

बड़े किसान और मध्यम किसान

सरकार बताये कहां गए 18 लाख आवास : दीपक बैज

रायपुर/नवप्रदेश। भाजपा सरकार ने दावा किया था कि केन्द्र ने प्रधानमंत्री आवास के लिये 18 लाख आवासों की स्वीकृति हो गयी है। छत्तीसगढ़ में 18 लाख नए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की साथ सरकार ने अभी तक एक भी नए हितग्राही को आवास निर्माण के लिए एक नया पैसा नहीं दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय सरकार के तथाकथित प्रधानमंत्री



आवास केवल विज्ञापनों और होर्डिंग तक ही सीमित रह गया है, हकीकत भाजपा की सरकार आने के बाद से छत्तीसगढ़ में एक भी हितग्राही के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। ऊटे पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूषेश बघेल सरकार के द्वारा -छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना- भी अधोषिठ तौर पर बंद कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से -मोर जमीन मोर मकान- योजना पर भी ग्रहण लग चुका है। साय सरकार की दुर्भावना के चलते लाखों गरीबों से उनका पक्का

आवास का हक छिन गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार का वादा था 2022 तक हर गरीब के सिर पर पक्का छत देने का लेकिन 100 दिन में महंगाई कम करने, कालाधन वापस लाकर सभी के बैंक खातों में 15-15 लाख देने और 2 करोड़ रोजगार हर साल की आवास निर्माण के लिए एक नया पैसा नहीं दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय सरकार के तथाकथित प्रधानमंत्री आवास केवल विज्ञापनों और होर्डिंग तक ही सीमित रह गया है, हकीकत भाजपा की सरकार आने के बाद से छत्तीसगढ़ में एक भी हितग्राही के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। ऊटे पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूषेश बघेल सरकार के द्वारा -छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना- भी अधोषिठ तौर पर बंद कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से -मोर जमीन मोर मकान- योजना पर भी ग्रहण लग चुका है। साय सरकार की दुर्भावना के चलते लाखों गरीबों से उनका पक्का

सीएम साय ने मोबाइल मेडिकल यूनिट व प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के ऐम्स परिसर में -निश्चय निरामय छत्तीसगढ़- 100 दिवसीय जांच व उपचार अभियान के दौरान लोगों में जागरूकता व टीबी जांच हेतु संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट व प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर संभाग के लिए एक एक वाहन शामिल हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उपस्थित थे।



संदेहास्पद टीबी मरीजों का स्पोर्ट पर ही टीबी रोग का पता लगाया जा सकेगा। मोबाइल मेडिकल यूनिट

द्वारा ए.आई. तकनीक से हैंड हेल्ड एक्स रे, डब्ल्यू-टीबी जांच व चैनल वाले टर्नूनाट मशीन से टीबी

के संभावित मरीजों की तुरंत एक्स रे द्वारा जांच एवं उपचार किया जाएगा।

बस्तर के तोकापाल की बबीता नाग ने मुख्यमंत्री को बांधा निरामय सूत्र

रायपुर/नवप्रदेश। एम्स रायपुर के आर्टिथोरियम में आज निश्चय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम अंतर्गत 100 दिनों तक टीबी, मलेरिया एवं कुछ रोगियों की पहचान की जाएगी तथा उनका उपचार किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे लोगों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने



टीबी और कुछ जैसी बीमारियों से लड़ाई लड़ी और आज स्वस्थ जीवन का आनंद उठा रहे हैं। इन्हीं मे से एक हैं बस्तर के तोकापाल की रहने वाली बबीता नाग जो कुछ समय पहले तक टीबी के रोग से पीड़ित थीं। इन्होंने सरकारी अस्पताल में अपनी जांच करायी और शासन की योजनाओं का

लाभ लेते हुए समय पर दवाइयों और पोषण आहार का सेवन किया। इसकी वजह से बबीता आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। बबीता ने अपने स्वस्थ होने का श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिया है जिन्की पहल की वजह से वो टीबी जैसी बीमारी के प्रति जागरूक हो सकीं और समय पर अपना इलाज कराया।

निहारिका कमेटी के अध्यक्ष को फेडरेशन ने सौंपा ज्ञापन

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने मंत्रालय में शासन द्वारा गठित निहारिका कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती निहारिका बारीक से भेंटकर प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में विस्तार से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा गया।

फेडरेशन के प्रांतीय सयोजक कमल वर्मा ने बताया कि फेडरेशन की प्रांतीय बैठक में तय किए गए मुद्दों को लेकर निहारिका कमेटी के समझ अपना पक्ष रखा है। जिसमें प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को भाजपा घोषणा पत्र अनुसार केन्द्र के समान देय तिथि से महंगाई भता दिया एवं जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ते के एरियस को मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68 (2)

अनुसार भविष्य निधि खाते में समायोजित करने, लिपिक सहित विभिन्न संवर्ग के वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करे,प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान क्रमशः 8,16, 24 एवं 32 वर्ष देने,अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 करने,प्रदेश के सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को अन्य कर्मचारियों के समान त्रिस्तरीय वेतनमान स्वीकृति करने,केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता कार्यभारित /आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों को समान वेतन के रिक्त पदों पर लिया एवं जुलाई 2019 से लंबित महंगाई संपत्ति विवरण ऑनलाइन करने आदि शामिल है।

डॉ. स्मित को मिला कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का फैलो सम्मान

रायपुर/नवप्रदेश। डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. (प्रो.) डॉ. स्मित श्रीवास्तव को कार्डियोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया का फैलो सम्मान प्राप्त हुआ है। इसी के साथ यह सम्मान प्राप्त करने वाले राज्य के पहले कार्डियोलॉजिस्ट बने हैं डॉ. स्मित श्रीवास्तव। डॉ. स्मित श्रीवास्तव को आज लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फैलो का सम्मान देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के हाथों मिला है। उन्हें एफ़सीएसआई प्रमाण



पत्र और पदक से सम्मानित किया गया। लखनऊ में आयोजित प्रतिष्ठित फैलोशिप दीक्षांत समारोह में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे। देशभर से मात्र 15 कार्डियोलॉजिस्ट इस सम्मान के लिए चयनित किए गए हैं। इसके अलावा डॉ. स्मित को

05 से 08 दिसंबर को आयोजित कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 76 वें वार्षिक सम्मेलन की वैज्ञानिक समिति में राष्ट्रीय संकाय के रूप में आमंत्रित किया गया है। विदित हो कि कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्य लक्ष्य

कार्डियोवैस्कुलर रोगों (सीवीडी) और उसके बाद होने वाली मृत्यु दर की रोकथाम और उन्मूलन की दिशा में काम करना है। इसका उद्देश्य लोगों में कार्डियोवैस्कुलर रोगों के कारणों और प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह सोसाइटी पर्यावरण और जीवनशैली के साथ कार्डियोवैस्कुलर रोगों के सह-संबंध के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता के स्तर को बढ़ाने की दिशा में काम करता है। सोसाइटी का वर्तमान ध्यान गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और कार्डियोवैस्कुलर रोगों की रोकथाम के लिए बाद के नए मार्गों पर है।

धान खरीदी केंद्रों में हमाली, फिर भी किसानों से ली जा रही है हमाली की राशि!

बैकुंठपुर /नवप्रदेश। कोरिया जिले में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 14 नवम्बर से चालू है जहाँ इस वर्ष ज्यादा वर्षा के कारण फसल में रोग लगने से उत्पादन प्रभावित होने की संभावना के बावजूद भी समितियों में धान की आवक बढ़ी है। जहाँ शासन द्वारा किसानों को इस वर्ष एक एकड़ में 21 किबंटल की खरीदी की मात्रा भी निर्धारित की गई है वहीं 3100 की घोषणा को देखते हुए किसान अपने खातों में पंजीयन अनुसार खाते में धान की पूरी मात्रा देकर धान की विक्रय कर रहे है। वहीं शासन द्वारा किसानों को सोसायटी में किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए प्रासंगिक व्यय की राशी भी जारी कर दी गई ताकि समितियों में धान लेकर आने वाले किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो इसके बावजूद भी कोरिया जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है वहीं इस वर्ष हर खरीदी केंद्रों में कलेक्टर कोरिया ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है जो कि समिति में जाकर किसानों की

समस्या से रूबरू होंगे व हो रही समस्या को तत्काल जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे ,इसके बावजूद भी किसानों से मिली जानकारी अनुसार शायद ही किसी खरीदी केन्द्र में किसी ने किसानों की समस्या का हल किया हो वहीं किसान इस कारण विरोध नहीं कर पाता की कहीं हमारा धान न खरीदा जाये या समितियों द्वारा शिकायत करने वाले किसानों को अनावश्यक परेशान किया जाता है जिस कारण किसी के द्वारा भी कोई शिकायत नहीं की जाती है जिस कारण समितियों में हर किसान समिति प्रबंधकों के अनुसार ही धान विक्रय करने को मजबूर है वहीं जिले से गठित निगरानी समिति में नोडल अधिकारी भी किसी प्रकार की गड़बड़ी होने से इंकार कर रहे है जो कि समझ से परे है। इस वर्ष जिले पे धान खरीदी के लिए 21 खरीदी केंद्र बनाये गए है जहाँ इस वर्ष शासन द्वारा धान



अनुसार जिले में धान खरीदी में जहा पूरी तरह पारदर्षिता अपनाने के दावे किए जा रहे है किंतु वास्तविकता कुछ और ही है जहाँ किसानों का शोषण किया जा रहा है जिससे कई समितियों में किसानों की समस्याये कम होने के बजाय बढ़ रही है। वहीं अधिकारी सही तरीके से धान

खरीदी होने का दावा कर रहे है ।मिली जानकारी अनुसार शासन ने हर खरीदी केंद्रों में किसानों से धान खरीदी के दौरान नपाई टोलाई ,सिलाई व बोरा को फट तक पहुंचाने व इसकी सुरक्षा के लिए जानकारी के पहले कार्डियोलॉजिस्ट बने हैं डॉ. स्मित श्रीवास्तव। डॉ. स्मित श्रीवास्तव को आज लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फैलो का सम्मान देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के हाथों मिला है। उन्हें एफ़सीएसआई प्रमाण

रही है जबकि समिति को हमाली राशि का भुगतान करना है ,जिससे कही न कही किसानों के शोषण के साथ ही सुविधा के नाम पर लाखों रूपए का खेल भुगतान के आहरण के दौरान होने की संभावना है वहीं जिला प्रशासन व राजनीतिक पार्टी की निगरानी समिति ने इस पर अब तक कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की जो चुकी है इसके बावजूद जिले के कई समितियों में किसानों से खरीदी केंद्रों पर ही एक बोरे के भरई टोलाई ,सिलाई व फट तक चढ़ाने के नाम पर 10 से 12 रूपए समिति में कार्य कर रहे हमाली द्वारा लिए जा रहे है जिसकी जानकारी जिले के अधिकारियों को अब तक नहीं है जब

की शासन द्वारा 1 किबंटल पे यदि सुरक्षा को छोड़ दिया जाये तो मिली जानकारी अनुसार 8 से 9 रूपए दिए जा रहे है आखिर यह राशि कहा जा रही है । वहीं भसवाल यह उठता है कि आखिर जिले के कई समितियों में किसके निर्देश पर किसानों से यह हमाली राशी ली जा

रही है जबकि समिति को हमाली राशि का भुगतान करना है ,जिससे कही न कही किसानों के शोषण के साथ ही सुविधा के नाम पर लाखों रूपए का खेल भुगतान के आहरण के दौरान होने की संभावना है वहीं जिला प्रशासन व राजनीतिक पार्टी की निगरानी समिति ने इस पर अब तक कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की जो चुकी है इसके बावजूद जिले के कई समितियों में किसानों से खरीदी केंद्रों पर ही एक बोरे के भरई टोलाई ,सिलाई व फट तक चढ़ाने के नाम पर 10 रूपए की राशि सुविधा के नाम पर लेकर समितियों द्वारा लाखों रूपए के गेतमाल पर चुपी साधे रहना समझ से परे है जब की यदि देखा जाये तो इस वर्ष अब तक कोरिया जिले में किसानों से लगभग 22977.92 मे0 टन धान की खरीदी अब तक हो चुकी है । बहरहाल कलेक्टर कोरिया ने किसानों को खरीदी केंद्रों पर किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये है

हमाली समिति को देने का निर्देश
जयपाल एक्का ,प्रभारी पंजीयक सहकारिता विभाग बैकुंठपुर - कोरिया -इस वर्ष जिले में खरीदी में पूरी पारदर्षिता है कहि भी हमाली राशि लेने की शिकायत किसानों से नहीं मिली है वहीं हमाली राशि के संबंध में सभी समिति को नोटिस जारी किया गया है यदि जाच में पाया गया तो कार्यवाही होगी । वहीं सभी समितियों में हमाली राशि किसानों से नही लेने के सम्बंध में सूचना पटल पर उल्लेख का सख्त निर्देश है । किंतु अधिकारियों की उदासीनता के कारण हमाली के कारण किसानों को हो रही समस्या की जानकारी जिला प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रहा वहीं अधिकारी जाच के नाम पर केवल खानापूर्ति कर वापस आने मुख्यालय आ जा रहे हैं । वहीं किसी भी प्रकार की समस्या नहीं मिलने की बात कह रहे है ।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना उपभोक्ताओं ने छत पर बनाया खुद का बिजली घर

कांकेर/नवप्रदेश। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को घरों तक पहुंचाकर उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत सौर ऊर्जा अपनाने वाले नागरिकों को सरकार की ओर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे इसकी लागत कम हो जाती है। जिले में इस योजना ने कई परिवारों की आर्थिक और ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया है। समीप के ग्राम डेलकाबोड निवासी श्रीमती सुमित्रा मंडवी ने चार किलो वॉट का सोलर ऑन-ग्रिड प्लांट लगाया, जिससे उन्हें 78 हजार रूपए की सब्सिडी का लाभ मिला। उन्होंने बताया कि उक्त योजना से विद्युत देयक में 80 प्रतिशत तक की बचत होती है। सरकार की सब्सिडी ने सौर ऊर्जा



आर आंधक आसान बना दिया है। इसी तरह ग्राम पंडरीपानी के विद्युत उपभोक्ता श्री धनेश साहू ने उक्त योजना के तहत अपने घर की छत पर तीन किलो वॉट का सोलर ऑन-ग्रिड रूप टॉप प्लांट स्थापित किया है। श्री साहू ने बताया कि इस योजना के तहत मिलने वाले अनुदान से बिजली की और भी किफायती बना दिया है। यह योजना आम आदमी के लिए वरदान है। इसी प्रकार सुभाष वार्ड

ने कहा- 'सौर ऊर्जा ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है और सरकार की मदद से यह संपन्न हो पाया है।'

किलोवॉट के अनुसार 30, 60, 78 हजार की मिलेगी सब्सिडी

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता श्री सतीश किण्डो ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार ने सौर ऊर्जा सिस्टम बनाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया है। इसके तहत एक किलो वॉट में 120 तक की बिजली प्री रहेगी। इसमें 30 हजार रूपए की सब्सिडी दी गई है, जो एक छोटे घर के लिए लाभदायक है। इसी तरह दो किलो वॉट में 240 से अधिक यूनिट तक की बिजली प्री रहेगी। इसके तहत

60 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाएगी, जो एक मध्यम घर के लिए लाभदायक होगा। इसी तरह तीन किलो वॉट में 360 तक यूनिट तक बिजली प्री रहेगा, इसके तहत 78 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाएगी, जो एक बड़े घर के लिए लाभदायक है। उन्होंने बताया कि 'प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना' के तहत लगाए जाने वाले रूप टॉप सोलर पैनल की 25 साल की वारंटी रहेगी तथा अधिकृत वेंडर द्वारा 05 साल तक प्लांट का संधारण किया जाएगा। ने छत्तीसगढ़ के परिवारों को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त किया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है। उन्होंने जिले के उपभोक्ताओं से शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने की अपील की है।

कैसे करें आवेदन

कार्यपालन अभियंता किण्डो ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने हेतु उपभोक्ता को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए pmsuryaghar.gov.in पर रजिस्टर/पंजीयन कर राज्य का चयन करना होगा, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के विकल्प को चुनना होगा तथा इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूमर नंबर का चुनाव कर अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज करना होगा। इसके बाद कन्ज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगिन करके रूपटॉप सोलर के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद

अफ़वल मिलने के पश्चात विभाग में पंजीकृत वेंडर से सौर संयंत्र स्थापित कराना होगा। एक बार इंस्टालेशन पूरा हो जाने पर प्लांट का विवरण जमा करना पड़ेगा और नेट मीटर के लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि इसके उपरांत कमिशनिंग रिपोर्ट प्राप्त कर, अपना बैंक खाते का विवरण तथा निरस्त चेक पोर्टल के माध्यम से जमा करना पड़ेगा। 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता को सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए समीप के विद्युत कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

न्यूज गैलरी

कलेक्टर के निर्देश पर ओडिशा से आने वाले 150 बोरी धान लदा ट्रैक्टर जलत किया गया



कोंडागांव/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को 31000रु प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जा रही है। इस प्रक्रिया में बिजौलियों द्वारा किसानों के नाम पर ओडिशा से अवैध धान खपाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर पर विशेष चेकपोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत

कांग्रेस संविधान रक्षक अभियान के तहत रैली का आयोजन किया



कोंडागांव/नवप्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा प्राप्त निर्देश अनुसार सम्पूर्ण देश में संविधान रक्षक अभियान के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार कोंडागांव में 07 दिसंबर दिन शनिवार को संविधान रक्षक अभियान के तहत विशाल रैली का आयोजन किया गया। संविधान रक्षक अभियान बस्तर विधाय लखेश्वर बघेल जी के उपस्थिति में कांग्रेस भवन से निकलकर कोर्ट चौक स्थित डॉ भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति में माल्यार्पण कर नमन कर रेस्ट हॉस होते हुए गांधी चौक से शीतला मंदिर मंडी रोड होते हुए पुनः कांग्रेस भवन पहुंच रैली पश्चात संविधान सभा का आयोजन किया।

शासकीय अस्पतालों एवं चॉइस सेंटरों में बनाया जा रहा आयुष्मान वय वंदना कार्ड

कांकेर/नवप्रदेश। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन



आरोग्य योजना अंतर्गत कांकेर जिला में 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'आयुष्मान वय वंदना कार्ड पंजीयन' का कार्य सभी शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों एवं समस्त चॉइस सेंटरों में किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश शांडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को रूपये 5 लाख तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। 70 वर्ष से अधिक उम्र के हितग्राही जिनका पूर्व में आयुष्मान कार्ड बन चुका है, उन्हें भी दोबारा पंजीयन, ई-केवाईसी करवाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड में

एनएचएम कर्मचारियों की मांग अपूर्ण 8 को रायपुर में प्रांतीय बैठक

बड़े आंदोलन करने की रणनीति पर होगी चर्चा

कांकेर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश एन एच एम कर्मचारी संघ की बड़ी बैठक रविवार 8 दिसम्बर को गुरुदासीदास प्लाजा रायपुर में आयोजित होगा। जिसमें 33 जिलों के एन एच एम स्वास्थ्य कर्मचारी जुटेंगे, विधानसभा शीतकालीन सत्र 16 से 20 दिसम्बर को देखते हुए बनाया जा रहा है बड़ा आंदोलन करने की तैयारी किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष दीपक वर्मा ने बताया कि प्रदेश एन एच एम कर्मचारी अपने लंबित मांग नियमितीकरण स्थाईकरण घोषित 27व प्रतियुत वेतन वृद्धि सहित ग्रेड पेय स्केल सहित 18



बिंदु मांग को लेकर पिछले विधानसभा सत्र के दौरान भारी भारिश में विधानसभा घेरने निकले थे साथ ही विभिन्न मंच के माध्यम से मुख्य मंत्री विष्णु देव सांय उपमुख्यमंत्री अरुण साव विजय शर्मा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अधिकारी/कर्मचारियों ने शनिवार अवकाश के लिए सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन

कांकेर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला इकाई कांकेर के द्वारा-05 दिसंबर 2024 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कार्यक्षमता एवं उत्पादकता के उद्देश्य हेतु शनिवार को अवकाश घोषित एवं सेक्टर बैठक दिवस (शनिवार) को अन्य दिवस में प्रतिस्थापित करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया।छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक एफए 1-3/2022/1/5 दिनांक 02.02.2022 के माध्यम से शासन के समस्त विभागों के क ा य ा ल यी न (अधिकारी/कर्मचारियों) की कार्यक्षमता एवं उत्पादकता के उद्देश्य से माह के सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में जिस



प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला कार्यक्रम प्रबंधक इकाई में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को समस्त शनिवार को अवकाश प्रदान किया जा रहा है, उसी भांति विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों (कार्यालयीन स्टाफ) की कार्यक्षमता एवं उत्पादकता बढ़ाने शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक शनिवार को अवकाश प्रदान करने

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से थे शामिल
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला इकाई कांकेर जिला संरक्षक रोहित वर्मा, जिलाध्यक्ष दीपक वर्मा, प्रशांत झा, राकेश राजपूत, कोमल पटेल, संतानू बौध, लालिमा सोनवाली, कुमेश्वरी सिन्हा, सिद्धांत हलदर, शीतल साहू, अमित राय, रिंतेश जैन सहित एनएचएम/एड्स कंट्रोल के कर्मचारी/अधिकारीगण उपस्थित थे। उपरोक्त जानकारी जिला मीडिया प्रभारी डॉ विनोद वैद्य आकाश सिंह ठाकुर के द्वारा दी गई।

की आवश्यकता है।चूंकि विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक इकाई के सेवागत अधिकारी/कर्मचारियों को शासन से आदेशित अवकाश से वंचित हो रहे हैं, जिससे सभी कार्यालयीन स्टाफ में इस भेद-भाव एवं जनरन कार्य लिये जाने जैसी व्यवस्था से स्वयं को ठगा हुआ एवं मानसिक प्रताड़ित जैसे महसूस कर रहे हैं। निसंदेह इस प्रकार की दोहरी व्यवस्था कर्मचारियों में आक्रोशित भावना को जन्म देती है, जिससे वे अपना पूर्ण कार्यक्षमता का

उपयोग नहीं कर पाते एवं अपना शत-प्रतिशत योगदान देने में असमर्थ होते हैं। ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराना चाहेंगे की इसी प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या खण्ड चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार सेक्टर बैठक दिवस (शनिवार) को अन्य दिवस में प्रतिस्थापित कर वहां सेवागत कार्यालयीन अधिकारी/कर्मचारियों को प्रत्येक शनिवार को अवकाश प्रदान किया गया है।

सर्व आदिवासी समाज के बंद का कोंडागांव में व्यापक असर, व्यापारिक प्रतिष्ठान रहे पूरी तरह बंद

कोण्डागांव/नवप्रदेश। सर्व आदिवासी समाज ने जिले के आदिवासी महिलाओं के साथ बढ़ते अनाचार, अत्याचार पर रोक को लेकर 7 दिसंबर को एक दिवसीय बंद का कोंडागांव में व्यापक प्रभाव देखने को मिला। समाज ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार, शासकीय भर्ती में स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता और आदिवासी युवा प्रभाग के जिलाध्यक्ष यतीन्द्र छोटू सलाम के विरुद्ध सौंप गए ज्ञापन समेत कई मुद्दों पर अपनी मांगों को लेकर बंद का आह्वान किया था।जिसके चलते नगर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। चौपाटी मैदान में सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले सभा आयोजित की गई, जिसमें समाज के प्रमुख



सदस्यों और विभिन्न संगठनों ने भाग लेकर समर्थन जताया। सभा में वक्ताओं ने अपनी मांगों को रखते हुए महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लेकर थीं। बंद के दौरान नगर में किसी भी अग्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, पुलिस बल हर संवेदनशील स्थान पर तैनात किया था।

बाबा साहेब सेवा संस्था में डॉ.अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई

कोण्डागांव/नवप्रदेश। बाबा साहेब संस्था कोंडागांव में छत्तीसगढ़ एम्पलाइज वेल्फेयर एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त रूप से बाबा साहेब सेवा संस्था कार्यालय अंबेडकर चौक में शुक्रवार 06 दिसंबर 2024 को संस्था 7 वजे प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहेब डॉ.भीमराव अम्बेडकर जी का 69वां महापरिनिर्वाण दिवस की सभा की गई। इस दौरान बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्जलित करके एवं चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा इस अवसर बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के संरक्षक नेशनल



अवार्डेड आर्टिजन पंचू सागर, अधिवक्ता तिलक पांडे, प्रमोद भारती, अध्यक्ष मुकेश मारकंडेय, सचिव रमेश पोयाम, आमप्रकाश नाग, हितेंद्र श्रीवास, मंगड देवांगन, विनोद नेताम, झिटकु मरकाम, देवानंद चौरे, संदीप कोराम, अजाक्स पदाधिकारीगण जगमोहन भोयर, धवलसिंह पोटाई

छत्तीसगढ़ एम्पलाइज वेल्फेयर एसोसिएशन जिला कोंडागांव अध्यक्ष नरसिंह देव मंडवी, रमन ठाकुर, गरंजु नेताम, संदीप वासनिकर, सुनील बंजारे, ईसाईदाँ चौरे, तत्थसील चौरे,वेण्य मंडावी सहित संस्था के अन्य पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

प्रथम पेज का शेष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से ...

सदेश आए, जिसमें कहा गया था कि सदेश भेजने वाला बिश्नोई गिरिह का सदस्य है। इस सदेश में चेतावनी दी गई थी कि अगर सलमान खान ने पांच करोड़ रुपये नहीं दिए तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। भेजने वाले ने चेतावनी दी कि वह मैं सिक्कंदर हूँ गीत के लेखक को भी मार दोगा। हालांकि पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया था।

गृहमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा...

केंद्रीय मंत्री बस्तर ओलंपिक के समापन में भी शामिल होंगे। शर्मा ने बताया कि शाह 14 दिसंबर की रात को रायपुर पहुंचेंगे और 16 दिसंबर की शाम को वह दिल्ली लौट जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन और रायपुर में पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल

होंगे। इस दौरान शाह नक्सल अभियान से संबंधित बैठक भी लेंगे। शर्मा ने शाह के मिन्ट टू मिन्ट कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शाह 14 तारीख की रात 9-00 बजे दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। आगामी 14 दिसंबर को वह रात्रि विश्राम करेंगे। आगामी 15 दिसंबर की सुबह शाह पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवॉर्ड में शामिल होंगे। इसके बाद उसी दिन वह जगदलपुर के लिए रवाना होंगे जहां बैठक में जितने भी पुलिस कमांडर हैं व जिन्होंने नक्सल ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, वे शामिल होंगे। इसके बाद दूसरे दिन सुबह में वह शहीदों से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान शाह शहीद परिवार से मुलाकात भी करेंगे। शाह एक कैप का भ्रमण भी करेंगे। उसके बाद वापस रायपुर आएंगे, जहां

एलडब्ल्यू की समीक्षा बैठक भी होगी। उसके बाद शाम 4:00 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

दिल्ली कूच के लिए पहुंचे 60 किसान ...

भेज दिया गया। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन की तानाशाही चल रही है। आंदोलन को दबाने के लिए उनके नेताओं को जेल भेज दिया है। लेकिन किसान अपना हक लेकर रहेंगे। किसानों का जेल भरो आंदोलन जारी रहेगा।

नक्सलियों ने की मुखाबिरी के शक में आंगनबाड़ी ..

हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बीच बचाव करने पहुंचे बेटे के साथ हमलावरों ने हाथापाई की और लक्ष्मी की हत्या कर दी। लक्ष्मी पसम को दो बार पहले भी धमकी मिल चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक

हमलावरों ने कैम से 1 किलो मीटर वारदात को अंजाम दिया। रात को हुई इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। घटना की आधिकरिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में ..

सोलर प्लेट, हथियार बनाने की मशीन, बड़ी सेंदुके, तेल टिन, साबुन एवं अन्य नक्सली दैनिक उपयोगी सामग्री को सुरक्षा बलों द्वारा मौके पर नष्टीकरण की कार्यवाही किया गया। उक्त नक्सल विरोधी अभियान में नारायणपुर डीआरजी एवं बीएसएफ की संयुक्त कार्यवाही रही।

सीरिया: संघर्ष में ..

धीणज लड़ाई के बाद सीरियाई सशस्त्र बल हमा शहर से हट गए।

किसान ने कर्ज नहीं लिया फिर...

है, लेकिन यही कहानी अकेले जितेंद्र की

नहीं है. यादव राम वर्मा, राजकुमार वर्मा, शेखर वर्मा और प्रदीप वर्मा सहित कई किसानों को इसी तरह ठगा गया. इन किसानों ने न कभी लोन के लिए आवेदन किया, न ही उन्हें इसकी जानकारी थी।

औद्योगिक विकास के प्रयासों में

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नया इतिहास रचने जा रहा है। इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा लगभग 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है। इससे सोहागपुर, इटारसी, सिवनीमालवा, पिपरिया, पचमढी के स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और रोजगार के लिए होने वाला पलायन इन क्षेत्रों से रहेगा। आरआईसी में किये जा रहे निवेश के

कारण महज 2 से 3 वर्षों में ही संपूर्ण नर्मदापुरम क्षेत्र का आर्थिक परिदृश्य बदलेगा। नर्मदापुरम की कर्मशील जनता औद्योगिक विकास में सहायक बनेगी। नर्मदापुरम वन संपदा, भू-संपदा, बेहतर रोड और रेल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं के साथ औद्योगिक विकास के लिए सबसे अनुकूल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उज्जैन, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर के बाद अब 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम में हो रही है। औद्योगिक विकास के इन प्रयासों में नर्मदापुरम को कम समय में सबसे अधिक सफलता मिली है। निवेशकों को औद्योगिक पार्क मोहासा-बाबई की विशेषता तथा सरकार द्वारा दिए जा रहे वित्तीय अनुदान का सीधा फायदा निवेशकों को



न्यूज गैलरी

ईडी ने 388 करोड़ रुपये की नई संपत्ति जब्त

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए 5 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था, जिसका कुल मूल्य 387.99 करोड़ रुपये है। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव अंनिलाइन सट्टेबाजी मामले में चल रही धन शोधन जांच के तहत करीब 388 करोड़ रुपये की नई संपत्ति कुर्क की है। एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस मामले में छत्तीसगढ़ के कई उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों के कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इनमें चल संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों में मॉरीशस स्थित कंपनी तानो इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग लिमिटेड फंड की संपत्तियां, इएफपीआई और एफडीआई के माध्यम से दुबई स्थित हवाला ऑपरेटर हरि शंकर टिबरेवाल से संबंधित निवेश और छत्तीसगढ़, मुंबई व मध्य प्रदेश में कई सट्टेबाजी एप और वेबसाइटों के प्रमोटर्स, पैनल ऑपरेटर्स और प्रमोटर्स के सहयोगियों के नाम पर मौजूद संपत्तियां हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए 5 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था, जिसका कुल मूल्य 387.99 करोड़ रुपये है। इस मामले में एजेंसी टिबरेवाल से पूछताछ कर रही है।

अंडमान में बड़े पैमाने पर आयकर छापे जारी

नई दिल्ली। कोलकाता से आई एक आयकर टीम पोर्ट ब्लेयर के चर्च रोड, फीनिक्स बे, मरीन हिल्स, एबरडीन बाजार और दिलानीपुर इलाकों में कई कार्यालयों में छापेमारी कर रही है। बाबू लेन और जंगलीघाट इलाकों में भी तलाशी अभियान चल रहा है। आयकर विभाग के 120 से अधिक अधिकारी अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कई स्थानों पर तलाशी ले रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। आयकर अधिकारी ने बताया कि द्वीपसमूह के कुछ व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने में संदिग्ध अनियमितताओं के चलते 4 दिसंबर को तलाशी शुरू हुई थी और अभी भी कार्रवाई जारी है। अधिकारी ने बताया, कोलकाता से आई एक आयकर टीम पोर्ट ब्लेयर के चर्च रोड, फीनिक्स बे, मरीन हिल्स, एबरडीन बाजार और दिलानीपुर इलाकों में कई कार्यालयों में छापेमारी कर रही है। बाबू लेन और जंगलीघाट इलाकों में भी तलाशी अभियान चल रहा है। उन्होंने बताया कि एमजी रोड और गुरुद्वारा लेन स्थित कार्यालयों में भी इसी तरह की छापेमारी चल रही है। अधिकारी ने कहा, यह एक सुव्यवस्थित ऑपरेशन है और हम जल्द ही इसके निष्कर्षों का खुलासा करेंगे। हमें रिटर्न दाखिल करने में अनियमितता और जीएसटी से संबंधित मुद्दों का संदेह है।

पहली छमाही में, सरकार ने वित्त वर्ष 25 के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये के अपने पूंजीगत व्यय लक्ष्य का केवल 37.3 प्रतिशत खर्च किया

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा- तीसरी तिमाही में होगी मंदी की भरपाई

नई दिल्ली। आम चुनाव और पूंजीगत व्यय में कमी की वजह से पहली तिमाही में विकास की गति कम रही। इसका असर दूसरी तिमाही पर भी पड़ा है। पहली छमाही में, सरकार ने वित्त वर्ष 25 के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये के अपने पूंजीगत व्यय लक्ष्य का केवल 37.3 प्रतिशत खर्च किया। अब इस सुस्ती पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, सितंबर तिमाही में जीडीपी में मंदी व्यवस्थित नहीं थी और तीसरी तिमाही में बेहतर सार्वजनिक व्यय के साथ आर्थिक गतिविधि मंदी की भरपाई कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यह बात कही। भारत ने जुलाई-सितंबर वित्त वर्ष 25 में 5.4 प्रतिशत की

जीडीपी वृद्धि दर्ज की, जो सात तिमाहियों में सबसे कम थी। पहली तिमाही में वृद्धि 6.7 प्रतिशत थी। सीतारमण ने एक कार्यक्रम में कहा, "यह एक व्यवस्थित मंदी नहीं है। यह सार्वजनिक व्यय, पूंजीगत व्यय और इसी तरह की अन्य गतिविधियों में कमी की वजह से है... मुझे उम्मीद है कि तीसरी तिमाही इन सबकी भरपाई कर देगी। वित्त मंत्री ने कहा, "इसलिए, विकास दर की संख्या ऐसी चीज है जो जरूरी नहीं कि बुरी तरह प्रभावित हो। हमें कई अन्य कारकों पर जोर देने की जरूरत है।" वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अगले साल और उसके बाद भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आम चुनाव और पूंजीगत व्यय में कमी की वजह



से पहली तिमाही में विकास की गति कम रही। इसका असर दूसरी तिमाही पर भी पड़ा है। पहली छमाही में, सरकार ने वित्त वर्ष 25 के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये के अपने पूंजीगत व्यय लक्ष्य का केवल 37.3 प्रतिशत खर्च किया। वित्त मंत्री की टिप्पणी भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से चालू वित्त वर्ष के लिए अपने

विकास अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत करने के कुछ ही देर बाद आई। सीतारमण ने कहा कि विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में वैश्विक मांग में स्थिरता शामिल है, जिसने निर्यात वृद्धि को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, भारतीयों की क्रय शक्ति में सुधार हो रहा है, लेकिन भारत में, आपको पर्याप्त वेतन

की भी चिंता करनी होती है। हम इन कारकों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिनका भारत की अपनी खपत पर असर हो सकता है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 24 के लिए अपने आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष के लिए 6.5-7 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था। उन्होंने कहा, हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हर चुनौती में अवसर तलाशता है। कोविड-19 के दौरान चुनौती को सुधार लाने के अवसर के रूप में देखा गया। उस समय पांच मिनो बजट पेश किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक ने एक तरफ राहत, समर्थन, सहायता दी और दूसरी तरफ यह सुनिश्चित किया कि छोटे और उपेक्षित लंबित सुधार किए जाएं।

2025-26 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आठवां बजट होगा

सीतारमण ने बजट पूर्व परामर्श के लिए अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय हर साल विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं, अर्थशास्त्रियों और राज्य के अधिकारियों के साथ कई बजट-पूर्व परामर्श बैठकें आयोजित करता है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की औपचारिक प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट 2025-26 के लिए इनपुट और सुझाव एकत्र करने हेतु प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट-पूर्व बैठक की शुरुआत की।



विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं, अर्थशास्त्रियों और राज्य के अधिकारियों के साथ कई बजट-पूर्व परामर्श बैठकें आयोजित करता है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की औपचारिक प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। पिछले वर्षों की तरह, 2025-26 का

बजट 1 फरवरी को पेश किए जाने की उम्मीद है। 2025-26 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आठवां बजट होगा। सभी की निगाहें मोदी 3.0 कार्यकाल के शेष समय के लिए प्रमुख घोषणाओं और सरकार के दृश्यामी आर्थिक मार्गदर्शन पर होंगी। बैठक के बाद स्वदेशी जागरण मंच के सह-

संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा कि अर्थशास्त्री इस बात पर एकमत थे कि भारत को अपनी स्वयं की व्यापक विनिर्माण नीति की आवश्यकता है। महाजन ने संवाददाताओं को बताया, "हमने खाद्य मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन, राजकोषीय समेकन और कृषि क्षेत्र के लिए रणनीतियों पर सुझाव दिए। व्यक्तिगत आयकर को कम करने के लिए भी सुझाव दिए गए।" बैठक में उपस्थित प्रख्यात अर्थशास्त्री अनिल शर्मा ने बेरोजगारी को एक गंभीर मुद्दा बताया।

शर्मा ने कहा, हमने जिला स्तर पर कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया है। हालांकि यह राज्य सरकार की पहल प्रतीत होती है, लेकिन यदि केंद्र सरकार इसमें पहल करती है तो इससे रोजगार को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिल सकता है।" बैठक के दौरान कुछ अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिगत आयकर को कम करने की आवश्यकता दोहराई।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ लाएगी

एजीआई इन्फ्रा को बोर्ड से शेयर विभाजन की मंजूरी



दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण (एनसीएलएटी) ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. की दिवालिया कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। प्राधिकरण ने कहा, सभी मुद्दों पर विचार के बाद हमारा मानना ​​है कि एनसीएलटी के आदेश में हस्तक्षेप का आधार नहीं है।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लि. ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए सेबी के पास शुक्रवार को दस्तावेज जमा कराया है। इसके मुताबिक, प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह से प्रवर्तक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक के 10.18 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश है।

एजीआई इन्फ्रा लि. की परिचालन आय दूसरी तिमाही में 9 फीसदी बढ़कर 7,756.26 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई। बोर्ड ने कंपनी के शेयरों को 1.2 अनुपात में विभाजित करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए रिकॉर्ड तिथि की घोषणा शेयरधारकों की मंजूरी के बाद होगी।

धोखाधड़ी से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बैंक एआई और मशीन लर्निंग का प्रयोग करेंगे

नई दिल्ली। डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को धोखेबाजों से बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) सहित उन्नत तकनीकों को अपनाएं। यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों और भुगतान बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ डीएफएस के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया। डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को धोखेबाजों से बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) सहित उन्नत तकनीकों को अपनाएं। यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई),



सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों और भुगतान बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ डीएफएस के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया, विशेष रूप से अवैध लेनदेन के सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले खच्चर खातों की बढ़ती संख्या पर। वित्तीय सेवा विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि "बैंकों को वास्तविक समय में खच्चर खातों का पता लगाने, धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए बैंक

कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें बेहतर बनाने, आम नागरिकों को धोखेबाजों के झांसे में न आने के लिए अधिक से अधिक वकालत और जागरूकता लाने के लिए समाधान सहित उन्नत तकनीकों को अपनाने का निर्देश दिया गया था। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने नागरिकों की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया और इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कल्याधुनिक उपकरणों और प्रथाओं का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डाला।

1.51 अरब डॉलर बढ़कर 658.091 हुआ आंकड़ा

नई दिल्ली। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 29 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 1.51 अरब डॉलर बढ़कर 658.091 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई ने यह जानकारी दी। जारी आंकड़ों के अनुसार 29 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 2.061 अरब डॉलर बढ़कर 568.852 अरब डॉलर हो गईं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 29 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 1.51 अरब डॉलर बढ़कर 658.091 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पिछले रीपोर्टिंग सप्ताह में कुल भंडार 1.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 656.582 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया था।

तीन कैंसररोधी दवाओं की कीमतें कम की गईं, लोकसभा में दी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर कंपनियों को निर्देश दिया कि वे जीएसटी दरों में कमी और सीमा शुल्क से छूट के कारण इन दवाओं पर एमआरपी कम करें ताकि उपभोक्ताओं को कम करें और शुल्कों का लाभ दिया जा सके। इस बारे में केंद्रीय रसायन उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में क्या कहा, सरकार ने तीन कैंसर रोधी दवाओं ट्रेस्टुजुमैब डेक्वसटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुवलुमैब पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है। इन कैंसर रोधी दवाओं पर जीएसटी की दरें भी 12% से घटाकर 5% कर दी गईं। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने अधिसूचना



30/2024 दिनांक 23.07.2024 के तहत तीन कैंसर रोधी दवाओं अर्थात ट्रेस्टुजुमाब डेक्वसटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुवलुमाब पर सीमा शुल्क को शून्य करने का एलान किया है। सरकार ने अधिसूचना संख्या 05/2024 दिनांक 08.10.2024 के तहत इन कैंसर रोधी दवाओं पर जीएसटी दरें भी 12% से घटाकर 5% कर दी हैं। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ,

2013) के अनुसार, दवाओं/फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में लागू कर और शुल्क शामिल होते हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर कंपनियों को निर्देश दिया कि वे जीएसटी दरों में कमी और सीमा शुल्क से छूट के कारण इन दवाओं पर एमआरपी कम करें ताकि उपभोक्ताओं को कम करें और शुल्कों का लाभ दिया जा सके। कंपनियों को कीमतों में बदलाव के बारे में जानकारी देने के लिए फॉर्म दाखिल करने का निर्देश किया गया। उसके जवाब में दवा निर्माताओं ने इन दवाओं पर एमआरपी कम कर दी और एनपीपीए के पास सूचना दाखिल कर दी।

टीवी चैनलों पर अश्लील विज्ञापनों के खिलाफ 73 शिकायतें

नई दिल्ली। राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरगन ने कहा कि शिकायतों का तीन स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा उचित ढंग से समाधान किया गया। मुरगन ने कहा कि केवल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियमों के तहत स्थापित तंत्र में प्रसारकों द्वारा स्व-नियमन, प्रसारकों के स्व-नियामक निकायों द्वारा स्व-नियमन और केंद्र सरकार की निगरानी प्रणाली शामिल है। सरकार ने संसद को बताया है कि पिछले तीन वर्षों में नियामक संस्थाओं को निजी टेलीविजन चैनलों पर अश्लील और फूहड़ विज्ञापनों के खिलाफ 73 शिकायतें प्राप्त

हुई हैं। राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरगन ने कहा कि शिकायतों का तीन स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा उचित ढंग से समाधान किया गया। मुरगन ने कहा कि केवल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियमों के तहत स्थापित तंत्र में प्रसारकों द्वारा स्व-नियमन, प्रसारकों के स्व-नियामक निकायों द्वारा स्व-नियमन और केंद्र सरकार की निगरानी प्रणाली शामिल है। सरकार ने संसद को बताया है कि पिछले तीन वर्षों में नियामक संस्थाओं को निजी टेलीविजन चैनलों पर अश्लील और फूहड़ विज्ञापनों के खिलाफ 73 शिकायतें प्राप्त

हुई हैं। राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरगन ने कहा कि शिकायतों का तीन स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा उचित ढंग से समाधान किया गया। मुरगन ने कहा कि केवल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियमों के तहत स्थापित तंत्र में प्रसारकों द्वारा स्व-नियमन, प्रसारकों के स्व-नियामक निकायों द्वारा स्व-नियमन और केंद्र सरकार की निगरानी प्रणाली शामिल है। सरकार ने संसद को बताया है कि पिछले तीन वर्षों में नियामक संस्थाओं को निजी टेलीविजन चैनलों पर अश्लील और फूहड़ विज्ञापनों के खिलाफ 73 शिकायतें प्राप्त



आदेश जारी करके उचित कार्रवाई की जाती है। एक अलग प्रश्न के उत्तर में, मुरगन ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों को आईटी (मध्यवर्ती) दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के भाग- दृढ़दृढ़ के तहत आचार संहिता का पालन करना

आवश्यक है। मंत्री ने कहा, ये संहिताएं स्व-नियामक प्रकृति की हैं। मुरगन ने कहा कि इन आचार संहिताओं के तहत प्रकाशकों को ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं करनी होगी जो कानून द्वारा प्रतिबंधित हो और नियमों में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु-आधारित स्व-वर्गीकरण पांच श्रेणियों में करना होगा। उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि इस प्रकार का स्व-वर्गीकरण करते समय, ऐसी सामग्री में दर्शाए गए काल के संदर्भ तथा उस देश और लोगों के सम्कालीन मानकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिनसे ऐसी सामग्री संबंधित है।

दास बोले- सिर्फ व्यापार को जोखिम मुक्त करने पर हमारा ध्यान

नई दिल्ली। ब्रिक्स मुद्रा से जुड़ी चर्चा पर बोलते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यह विचार समूह के एक सदस्य की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस पर कुछ चर्चाओं के अलावा कोई प्रगति नहीं हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिदास दास ने शुक्रवार बताया कि भारत की अपने व्यापार को डॉलर मुक्त करने की कोई योजना नहीं है और वह केवल अन्य तरीकों से जोखिम कम करने पर विचार कर

रहा है। वह अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी से संबंधित उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि यदि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर से दूर जाने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें 100 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। दास ने यहां केंद्रीय बैंक मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, जहां तक भारत का सवाल है, हमने डॉलर को समाप्त करने आदि के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। ब्रिक्स मुद्रा के बारे में उन्होंने कहा कि यह विचार समूह के एक सदस्य की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

नई दिल्ली। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव 79,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। हालांकि, चांदी 300 रुपये की गिरावट के साथ 93,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव भी शुक्रवार को 78,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव 79,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। हालांकि, चांदी 300 रुपये की गिरावट के साथ

93,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। गुरुवार को चांदी 93,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव भी शुक्रवार को 78,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा।

मल्टी कम्पोजिटि एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर वायदा कारोबार में फरवरी डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 181 रुपये यानी 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 76,657 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। जानकारी के अनुसार, एमसीएक्स पर सोने में मामूली बढ़त दर्ज की गई,



क्योंकि बाजार शाम को गैर-कृषि वेतन और बेरोजगारी के महत्वपूर्ण आंकड़ों का इंतजार कर रहा है। एलकेपी सिव्योरिटीज के कम्पोजिटि और करेंसी

के उपाध्यक्ष शोध विश्लेषक जतीन त्रिवेदी ने कहा, फेड के नीतिगत दृष्टिकोण को आकार देने के लिए ये मीट्रिक्स महत्वपूर्ण हैं। जबकि सोना

सकारात्मक रख बनाए हुए है। मार्च डिलीवरी वाले चांदी अनुबंध की कीमत 426 रुपये या 0.46 प्रतिशत बढ़कर 92,850 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स सोना वायदा 0.42 प्रतिशत बढ़कर 2,659.60 डॉलर प्रति औंस हो गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि अपेक्षा से अधिक मजबूत अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़े फेड को इस महीने ब्याज दरों में कटौती रोकने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिसका सोने की कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।



